

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2

देहरादून : दिनांक : 15 जनवरी, 2009

विषय: सिविल जज(जू०डि०) न्यायालय परिसर, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में श्रेणी-1 के 01 आवास, बाररूम, कैन्टीन एवं सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3878/यू०एच०सी०/एडमिन.ब्री/IX-b/2008, दिनांक 16.10.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल जज(जू०डि०) न्यायालय परिसर, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में श्रेणी-1 के 01 आवास, बाररूम, कैन्टीन एवं सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु प्रेषित रु० 17,54,000/- के आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित धनराशि रु० 17,35,000/- (सत्रह लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु० 17,35,000/- (सत्रह लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाय ।
- (3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी राशि स्वीकृत की गयी है ।
- (4) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (5) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय ।
- (6) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय ।
- (7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

- (8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।
- (9) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशाली अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (10) निर्माण इकाई कार्य 31.3.2009 तक समाप्त करते हुए स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण, उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं स्तान्तरण प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
- (11) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के आयोजनागत पक्ष में लेखा-शीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-00-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-134P/XXVII(5)/08, दिनांक 14.1.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)

सचिव ।

संख्या-36-दो(8)/XXXVI(2)/08-70-दो(1)/03-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल ।
- 4- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडौन, गढ़वाल ।
- 5- नियोजन विभाग, वित्त अनुभाग-5/एन०आई०सी० ।
- 6- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

()
(के०पी०पाटनी)

अनु सचिव ।